

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

80/11/226

दीव्यपाल vs (सुनवाई का)

तारीख  
परी

2011/00038 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

509

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में है

श्री लक्ष्मी शर्मा श्री

एन. एम. राजवाड़ा

30/9/2019

पत्रावली पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 04 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 04 ने आपत्ति की कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2011 द्वारा विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 226, 227, 145, 146 वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद से मिट्टी नहीं उठाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.03.2011 के विरुद्ध यह अपील चलने योग्य नहीं है तथा अपील न्यायालय हाजा में वर्ष 2011 में प्रस्तुत की गई और अभिभाषक अपीलांट शेष रेस्पोंडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं कर रहे हैं इसलिए अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील चलने योग्य है किन्तु धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत अन्तरिम स्थगन आदेश की विरुद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 08.3.2011 को प्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 04 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया तथा विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 226, 227, 145, 146 वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद से मिट्टी नहीं उठाने से अप्रार्थीगण/अपीलांटस जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था जिसके विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है, जो अन्तरिम स्थगन आदेश है। चूंकि अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

  
राजस्व अदालत प्राधिकारी  
अजमेर